देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 07.03.2025
समय 0720

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश सरकार, नारी सशक्तीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 'महिला सारथी' योजना की शुरुआत करेगी।
- देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना परिसर में विश्व स्तरीय सार्वजनिक पार्क बनाया जाएगा, राष्ट्रपति 20 जून को रखेंगी आधारशिला।
- सी.आई.एस.एफ में अगले दो वर्षों में 20 हजार से ज्यादा कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
- प्रकृति को समर्पित वंसतोत्सव आज से राजभवन देहरादून में शुरू होगा।

महिला सारथी योजना

प्रदेश सरकार, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 'महिला सारथी' योजना की शुरुआत करने जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा या परित्यक्ता हों। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग, महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दे रहा है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। श्रीमती आर्या ने बताया कि पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना 10 ई–स्कूटी और 2–2 ई–ऑटो रिक्शा व ई–टैक्सी कार के साथ शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले छह माह पायलेट प्रोजेक्ट का परिणाम देखने के बाद इसका विस्तार प्रदेश के अन्य शहरों में किया जाएगा। इन वाहनों के संचालन के लिए प्रोफेशनल मोबाइल एप बनाया गया है, जो करीब वैसा ही है जैसा ऑनलाइन वाहन बुक करने वाली कमर्शियल कंपनियों के एप में होता है। श्रीमती आर्या ने बताया कि वाहनों में महिला चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर कई फीचर शामिल किए गये हैं। इन वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग नियमित रूप से होगी, ताकि महिला चालक या सवारी में से किसी को भी सुरक्षा संबंधी समस्या होने पर तुरंत मदद मिल सके। इस योजना में पुलिस और परिवहन विभाग भी शामिल हैं।

सार्वजनिक पार्क

देहरादून स्थित राष्ट्रपति आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय सार्वजनिक पार्क बनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 20 जून इसकी आधारशिला रखेंगी। इसी दिन राष्ट्रपति आशियाना, आमजन के लिए खोला जाएगा। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देहरादून में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह जानकारी दी गई। इस पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पार्क का पूरा विकास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा इस पार्क को वर्ष 2026 में उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया जाएगा। डॉ. गुप्ता ने बताया कि उत्तराखण्ड की जनता के लिए खोला जाने वाला यह पार्क एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में काम करेगा। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएँ, नवीन डिज़ाइन, टिकाऊ विशेषताएँ होंगी और यह हरियाली, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। उन्होंने बताया कि इस विशाल हरित

क्षेत्र में बहु–गतिविधि क्षेत्र, साइकिलिंग ट्रैक, विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं, बच्चों के खेल क्षेत्र, पिकनिक लॉन, पैदल व जॉगिंग ट्रैक, वन प्रकृति पथ और जल सुविधाओं के साथ और कई अन्य आकर्षण भी यहां देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये पहल भागीदारी पूर्ण शासन और समुदाय–संचालित विकास के प्रति राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून नगर निगम में निविदा प्रक्रिया में हुई धांधली की जांच अपर महानिदेशक विजिलेंस से करने और दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान देहरादून नगर निगम के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वे उच्च न्यायालय के अब तक के आदेशों में दर्ज विभिन्न टिप्पणियों सहित सभी कागजात 7 मार्च की शाम 4 बजे तक अपर पुलिस महानिदेशक विजिलेंस को सौंपेंगे।

वेव्स

इलेक्ट्रॉनिक संगीत और डी.जे के क्षेत्र में इच्छुक लोगों के पास अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। वर्ल्ड ऑडियो एंड वीडियो एंटरटेनमेंट समिट (वेव्ज़) 2025 के तहत आयोजित ''रेज़ोनेट : द ईडीएम चैलेंज'' की पंजीकरण तिथि अब 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। यह प्रतियोगिता भारतीय संगीत उद्योग और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ''क्रिएट इन इंडिया'' पहल के तहत आयोजित की जा रही है, जो भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक–ईडीएम हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रतियोगिता दुनिया भर के संगीतकारों, निर्माताओं और डी.जे के लिए खुली है, जो ईडीएम में दक्षता रखते हैं। विजेताओं को वैश्विक मंच मिलेगा, जहां वे संगीत जगत के दिग्गजों के सामने अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे।

''रेज़ोनेट : द ईडीएम चैलेंज'' का ग्रैंड फिनाले पहली से 4 मई को मुंबई में होगा, जहां शीर्ष 10 फाइनलिस्टों को इंडस्ट्री के दिग्गजों, संगीत निर्माताओं और दर्शकों के सामने प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा।

सीआईएसएफ

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल– सी.आई.एस.एफ. के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने कहा है कि अगले दो वर्षों में सी.आई.एस.एफ. में 20 हजार से ज्यादा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुरक्षा क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी कदम उठाए

जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल की एक महिला टीम अगले वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढाई के लिए गहन प्रशिक्षण ले रही है।

राजभवन वसंतोत्सव

राजभवन देहरादून में आज से तीन दिवसीय वंसतोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। पुष्प प्रदर्शनी 07 मार्च को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक और 08 व 09 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जनसामान्य के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। इस दौरान 15 विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और निर्णायक मंडल द्वारा चयनित विजेताओं को 9 मार्च को पुरस्कृत किया जाएगा। वसंतोत्सव में आईटीबीपी, आईएमए, पीएसी और होमगार्ड के बैंड आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल के निर्देशन में इस वर्ष वसंतोत्सव में कई नवीन पहल शुरू की गई हैं। उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा इस आयोजन में आने वाले लोगों की गणना एआई एप्लिकेशन के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए राजभवन के मुख्य द्वार पर एआई इनेबल कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा फीडबैक सिस्टम के लिए क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अपने सुझाव और अनुभव साझा कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य वसंतोत्सव को और अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाना है। वसंतोत्सव न केवल पुष्प प्रेमियों के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा, बल्कि यह नवाचार और तकनीकी विकास के नए आयाम भी स्थापित करेगा।

जन औषधि दिवस

आज जन औषधि दिवस है। यह दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। यह योजना नवंबर– 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना बाजार की तुलना में 50 से 80 प्रतिशत कम कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी गई दवाइयाँ भी प्रदान करती है। देश के सभी जिलों में अब 15 हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र कार्यरत हैं और इस योजना ने स्वरोजगार के लिए एक आशाजनक अवसर पैदा किया है, जो स्थायी और नियमित आय प्रदान करता है।

पुल क्षतिग्रस्त

चमोली जिले में जोशीमठ–मलारी मोटरमार्ग पर पांगतीनाला में बोल्डर गिरने से बैली ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। सीमा सड़क संगठन– बीआरओ के अनुसार पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवाजाही बाधित हो गई है। बीआरओ ने वैकल्पिक मार्ग बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

बैठक चमोली

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों को शत–प्रतिशत लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर लगाकर मजदूरों और कूड़ा बीनने वाले श्रमिकों का सर्वे किया जाए। जिलाधिकारी ने यात्रा मार्गों पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए विक्रय केन्द्र खोलने के लिए स्थान का चयन करने और विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को नियमानुसार प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए।

अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर्षिल–मुखबा भ्रमण की ख़बर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। विंटर टूरिज्म के लिये मोदी ने दिया 'घाम तापो' का मंत्र। इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है– प्रधानमंत्री ने गंगा के शीतकालीन गद्दीस्थल मुखबा से किया शीतकालीन यात्रा व पर्यटन को गति देने का शंखनाद। इसी ख़बर पर अमर उजाला प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है– उत्तराखंड का ही बन रहा यह दशक।

प्रधानमंत्री के संबोधन में दिये सुझावों पर राज्य सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। अमर उजाला समाचार पत्र के अनुसार पीएम के सुझावों पर अमल के लिये मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र। तेरह बिंदुओं पर अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट।

राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सारथी योजना शुरू करेगी। हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार छह माह के पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले सप्ताह महिलाओं को निःशुल्क सफर कराया जाएगा। यह योजना दस ई–स्कूटी, दो ई–ऑटो रिक्शा और दो ई–टैक्सी कार के साथ शुरू की जा रही है।

और, देहरादून के 47 वार्ड में कूड़ा उठान टेंडर की जांच शुरू। दैनिक जागरण समाचार पत्र की ख़बर है– हाइकोर्ट के निर्देश पर विजिलेंस की टीम ने नगर निगम से मांगे दस्तावेज।